भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .5469
25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी प्रभाग

5469. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बुनियादी ढांचा और परियोजना निगरानी प्रभाग (आई.पी.एम.डी.) ने खीरी क्षेत्र से संबंधित उन केंद्रीय परियोजनाओं (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या रेलवे ओवरब्रिज) की पहचान की है जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) क्या देरी के कारण उक्त परियोजनाओं की लागत में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित विभागों को उक्त परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क)और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर, 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी करने का अधिदेश प्राप्त है, और यह कार्य 'पैमाना' (राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण) नामक ऑनलाइन वेब निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

तदनुसार, इस मंत्रालय की वेबसाइट https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage. पर प्रकाशित फ्लैश रिपोर्ट में सभी चालू अवसंरचना परियोजनाओं का राज्यवार विवरण उपलब्ध है। हालांकि, डेटा की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है।

(ग): सभी हितधारकों (अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों/विभागों) को पैमाना पर उपलब्ध डेटा विश्लेषण के आधार पर उनकी परियोजना निष्पादन और चूक के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी

ओर से परियोजना निष्पादन के प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकें। इसके अतिरिक्त, हितधारकों के साथ मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से नियमित समन्वय साक्ष्य-आधारित निगरानी में योगदान प्राप्त होता है। इसके साथ ही, अनुकूलित डैशबोर्ड तक पहुँच प्रदान करने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोर्टल तक सीधी पहुँच प्राप्त हो पाए हैं।

भारत सरकार द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब को कम करने और उनमें तेजी लाने के लिए उठाए गए अन्य प्रमुख कदमों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति बैठकों के तहत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और कठोर परियोजना मूल्यांकन शामिल हैं।

*****